

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02

अंक : 93

जौनपुर, शुक्रवार 29 दिसम्बर 2023

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य : 2 रुपया

टीएम मोदी के अयोध्या आगमन से धर्मनगरी में होगा विकास के नए युग का सूत्रपात : योगी

एजेन्सी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार का प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही व दयाशंकर सिंह तथा महापौर अयोध्या सहित स्थानीय प्रशासन के साथ वर्षुअल बैठक कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। वर्ष 2023 की विदा वेला पर धर्मनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में 'विकास के नए युग' के प्रारंभ करने के लिए वाली गोली भी गोली। इस अवसर पर देश का ने केल एक नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उपहार मिलने जा रहा है, बल्कि अयोध्या को हजारों करोड़ के परियोजनाओं की परियोजनाओं के उपहार भी उत्सुक है। उन्हें



मिलेगा। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए तय रुट पर सुरक्षा और साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। स्थानीय मठ—मंदिरों को साजाएं। भव्य तोरण द्वारा तैयार कराएं। जगह—जगह सांस्कृतिक मंदिरियों द्वारा रुचिकर प्रस्तुतियों हों। प्रधानमंत्री के स्वागत मुहरोंवाली करोड़ की परियोजनाओं का उत्सुक है।

यथोचित स्थान दें। साधु—संतगणों द्वारा पृष्ठवर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनन्दन किया जाना है। उनसे संवाद बनाएं। यह रोड शो जनता के लिए है, ऐसे में जनधानमंत्री का समान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह अयोध्या द्वारा अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उत्सुक है। यह आयोजन के उपहार देने वाला होगा। यह आयोजन

अति महत्वपूर्ण है, इसके दृष्टिगत भावत सरकार के सहयोग से स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करें। जनसभा में आसपास के जनपदों से डेढ़ से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावना के दृष्टिगत सभी तैयारियां और अयोध्या को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं जनसभा में आने वाले नागरिकों की आवास्थुत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। भीड़ प्रबंधन पर फोकस करें। जनसभा खल एवं अन्य प्रमुख रथलों पर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और उन पार्किंगों के पास पर्याप्त जन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए। यथिक्षण की तैयारी करें। यह समारोह बड़ा है। बड़ी संख्या में जनधानीदारी होगी। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करें।

नए साल पर विश्वनाथ धाम आएगे 6 लाख श्रद्धालु

एजेन्सी

लखनऊ। न्यू ईयर पर महादेव की नगरी काशी में काफी धूम होगी। नए साल पर काशी के कारोबारीयों को वाली धूम मिलने वाला है। 1 जनवरी को बाबा विश्वनाथ धाम में 6-7 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। वहीं, जो अद्वालु मंदिर तक नहीं आ पाएं, उनके लिए मंदिर प्रशासन ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। 1 जनवरी से बाबा विश्वनाथ का ऑनलाइन रुप्रामिक भी शुरू हो रहा है। 700 रुपये में एक परिवार बाबा विश्वनाथ का घर बैठे रुप्रामिक कर सकता है। न्यू ईयर पर केवल ही वाराणसी में बढ़ती भीड़ और गंगा की दूधरी में जुड़ने वाले रुद्राद्युषों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नए साल पर कितनी ज्यादा भीड़ आने वाली है। वाराणसी के होटल, बोट्स, क्रूज सभी आउट हो चुके हैं।

कुछ 2 जनवरी तक पूरी तरह से बुकड़ है। यहां पर अब कोई नई बुकिंग नहीं हो रही है। लग्जरी होटल में वन नाइट 1 लाख रुपये से ऊपर तक चला गया है। नए साल पर देव दीपावली जैसा ही हाल होने वाला है। अलकनंदा क्रूजलाइन के चारों क्रूज और बाकी विश्वासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे कुमार दूबे नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका निरसारित करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र द्वारा लिंग और अन्य प्रमुख रथलों पर धूल तथा गंदगी आदि न हो। आवश्यकता नहीं है। आजाद के उकील ने कहा कि उनकी मुवकिल ए

एजेन्सी

प्रयागराज। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के वामलों में विद्युति परिषद को गुमराह करने से रोका जा सकता है क्योंकि ऐसा

व्यक्ति जानकारी छिपा सकता है। यह सूचना छिपाकर व्यक्ति ने लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में विकालत करने का लाइसेंस प्राप्त करा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने 21 दिसंबर को दिए अपने आदेश में कहा, "यह हैरत में डालने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने कहा, "सही तथ्य जो भी है, वर्तमान में यह शिकायत राज्य विभिन्न प्रशिक्षण के पास 25 सितंबर, 2022 से लंबित प्रतीत होती है। काफी समय युजर चुका है और अब तक उचित कार्यवाई ही जानी चाहिए थी। इन 14 मामलों में से चार मामलों में उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जा चुका

है। यह सूचना छिपाकर व्यक्ति ने वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त करा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने कहा, "सही तथ्य जो भी है, वर्तमान में यह शिकायत राज्य विभिन्न प्रशिक्षण के पास 25 सितंबर, 2022 से लंबित प्रतीत होती है। काफी समय युजर चुका है और अब तक उचित कार्यवाई ही जानी चाहिए थी। इन 14 मामलों में से चार मामलों में उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जा चुका है। यह सूचना छिपाकर व्यक्ति ने वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त करा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने कहा, "सही तथ्य जो भी है, वर्तमान में यह शिकायत राज्य विभिन्न प्रशिक्षण के पास 25 सितंबर, 2022 से लंबित प्रतीत होती है। काफी समय युजर चुका है और अब तक उचित कार्यवाई ही जानी चाहिए थी। इन 14 मामलों में से चार मामलों में उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जा चुका है। यह सूचना छिपाकर व्यक्ति ने वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त करा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने कहा, "सही तथ्य जो भी है, वर्तमान में यह शिकायत राज्य विभिन्न प्रशिक्षण के पास 25 सितंबर, 2022 से लंबित प्रतीत होती है। काफी समय युजर चुका है और अब तक उचित कार्यवाई ही जानी चाहिए थी। इन 14 मामलों में से चार मामलों में उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जा चुका है। यह सूचना छिपाकर व्यक्ति ने वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त करा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने कहा, "सही तथ्य जो भी है, वर्तमान में यह शिकायत राज्य विभिन्न प्रशिक्षण के पास 25 सितंबर, 2022 से लंबित प्रतीत होती है। काफी समय युजर चुका है और अब तक उचित कार्यवाई ही जानी चाहिए थी। इन 14 मामलों में से चार मामलों में उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जा चुका है। यह सूचना छिपाकर व्यक्ति ने वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त करा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 आपराधिक मामले हैं जिनमें से चार में वह दोषी करार दिया जा चुका है। उसने वकालत का लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति समाज को और विशेष रूप से कानून विरासी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारों को उदावान से रुकावा रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। अदालत ने कहा

सम्पादकीय

संसद के सवाल और विपक्ष का दायित्व

एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम शीतकालीन सत्र कई सुलगते सवालों को छोड़ गया है। इन सवालों के जवाब अभी गंभीरता से नहीं तलाशे गए, तो फिर देश में लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को उखड़ने से रोक पाना कठिन हो जाएगा। संसद पर हमला, 146 सांसदों के निलंबन के बाद अब ये तथ्य भी सामने आया है कि संसद में दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों द्वारा पूछे गए 264 सवालों को प्रश्नों की सूची से हटा दिया गया है। ये तमाम बाँतें भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ही हो रही हैं। 76 साल की आजादी और लोकतंत्र के दीर्घ अनुभव के बाद संसदीय कामकाज में परिपक्वता, धैर्य और संयम दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि हमें संसदीय तकाजे का ककहरा फिर से सीखना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस शीतकालीन सत्र में संसद पर एक और हमले की कोशिश की गई थी। एकबारगी यह हमला मौजूदा सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ दिखाई देता है। लेकिन अगर देश के एक तबके में भाजपा के शासन को लेकर इतनी अधिक नाराजगी व्याप्त है कि उसके लिए संसद पर हमले का दुस्साहस किया जाए, तो फिर यह नाराजगी चुनावी नतीजों में क्यों नहीं दिखाई देती। क्या संसद पर हमला करने वाले जानते नहीं थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या कानून की कड़ाई का अंदाज होने के बावजूद उन्होंने इस जोखिम को उठाया और अपना भविष्य, जीवन सब कुछ खतरे में डाला। कुछ लोगों का पूरे योजनाबद्ध तरीके से संसद के बाहर और भीतर आकर विरोध दिखाना किसी नजरिए से मामूली घटना नहीं है, लेकिन इस पर सरकार का रवैया देखकर यह लग ही नहीं रहा कि उसे किसी बात की चिंता हुई हो। क्या भाजपा अपने बहुमत को कवच इस कदर अभेद्य मानने लगी है कि उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि दो लोग संसद के भीतर आकर धुआं छोड़ गए। संसद पर हमले को लेकर भाजपा सरकार का रवैया जितना आश्चर्यजनक रहा, उससे कहीं अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि गृहमंत्री से सदन में जवाब की मांग कर रहे विपक्ष के 146 सांसदों को दो-तीन दिन के भीतर निलंबित कर दिया गया। सदन पर हुए हमले का जवाब अगर सदन में नहीं मांगा जाएगा, तो फिर उसके लिए कौन सी अन्य जगह उपयोगी है, यह भी भाजपा को बता देना चाहिए। लगभग डेढ़ सौ सांसदों का निलंबन काफी नहीं था कि संसद के दोनों सदनों की सूची से उन 264 सवालों को भी हटा दिया गया, जो विपक्षी सांसदों ने पूछे थे। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या इन सवालों से भी सदन की कार्रवाई में व्यवधान पड़ रहा था। उल्लेखनीय है कि सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सांसदों के नाम के तहत सूचीबद्ध किसी भी कार्य या उनके द्वारा पेश किए गए नोटिस पर विचार नहीं किया जाएगा। संसद के प्रश्नकाल और शून्यकाल सांसदों को प्रश्न पूछने और सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। इससे पहले भी विभिन्न सत्रों में सांसदों के निलंबन होते रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि निलंबन के साथ ही सांसदों के सवाल उठाने के संवैधानिक अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि खारिज किए गए सभी 264 सवाल

संसद की सुरक्षा के मसले से ही जुड़े थे, अगर जुड़े होते तब भी सरकार को इनका जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये सवाल जनता के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आधारित थे। जैसे राजद सांसद मनोज झा ने शिक्षा मंत्रालय से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के शब्दे पैमाने पर हटाने ये संबंधी सवाल किए थे। माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने समान नागरिक सहिता के कार्यान्वयन पर कानून मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। मगर अब इनका जवाब देने से मौजूदा सरकार बच गई है। सांसदों के निलंबन की कार्रवाई तो बाद में हुई, लेकिन संसद के नियमानुसार ये सवाल लगभग दो सप्ताह पहले ही लिखित में दिए जा चुके थे। किर इन्हें सूची से हटाना क्या न्यायोचित कहा जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर किए गए प्रदर्शन के दौरान कहा था कि 146 सांसदों को निलंबित करके लगभग 60 प्रतिशत जनता की आवाज को खामोश कर दिया गया है। संसद की सूची से सवालों को हटाना इस आरोप की ही पुष्टि करता है। शीतकालीन सत्र में उठे इन सुलगते सवालों के जवाब तलाशना इसलिए जरूरी है क्योंकि दांव पर जनता और देश का हित जुड़ा है। अब प्रश्न ये है कि अगर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और इनका संगी बन चुका मीडिया भी अगर इन सवालों से मुंह मोड़ ले तो फिर विपक्ष को क्या करना चाहिए। क्या विपक्ष लोकतंत्र बचाने के लिए केवल जुबानी जमा-खर्च करता रहेगा या राहुल गांधी जैसे दो-चार लोगों पर सङ्डकों पर उत्तरने का जिम्मा छोड़ देगा। अगर विपक्ष सङ्डक पर आता भी है तो क्या वह जनता तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर चुका है, या अब भी वो इंतजार में बैठा है कि कोई और आकर उसके हिस्से के काम करेगा। कायदे से अब विपक्षी सांसदों को अपने-अपने संसदीय क्षेत्र जाकर जनता से जुड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए। संसद के पटल से जिन सवालों को हटा दिया गया है, उन्हें जनता के बीच जाकर उठाना चाहिए, वहां तो निलंबन की कार्रवाई का कोई परिपत्र असरकारी नहीं रहेगा। विपक्षी नेताओं को भाजपा के सांसदों और मंत्रियों के क्षेत्रों में जाकर उन सवालों को उठाना चाहिए, जिनके जवाब संसद में दिए जाने चाहिए थे, मगर नहीं दिए गए। विपक्ष जब तक अपने अस्तित्व का अहसास जनता को नहीं कराएगा, तब तक सारे विरोध-प्रदर्शन और सवाल बैकार रहेंगे।

चंद्रमोहन

7 अक्तूबर को हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर हमले के बाद दुनिया भर में इजराइल के प्रति जो हमदर्दी थी वह गाजा पर लगातार और अंधारुद्ध बमबारी के बाद अब पूरी तरह से लुप्त हो गई है। इजराइल को अब एक क्रूर और असंवेदनशील बेसुध देश की तरह देखा जा रहा है जो बदले की भावना में इतना वह गया है कि हजारों बेकसूरों को मार चुका है। पूछा जा रहा है कि गाजा के कितने हजार और बच्चों का खून बहाने के बाद इजराइल की प्यास बुझेगी? हमास ने 1200 इजराइली मारे थे जबकि इजराइल हमास को तबाह करने की असफल कोशिश में 20000 फिलस्तीनियों को मार चुका है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। 5000 तो बच्चे ही मारे जा चुके हैं। जो कई सौ मलबे में दबे हैं वह अलग हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एनटोनियो गुटरेस का कहना है कि "गाजा बच्चों का कघीस्तान बन चुका है।" न्यूयार्क टाइम्स में पैट्रिक किंगसले ने लिखा है "पिछले तीन वर्षों में मैंने कघीब एक दर्जन बार इस इलाके की यात्रा की है। अब इसे पहचानना ही मुश्किल है। घरों की दीवारें या छतें, या दोनों गायब हैं। बहुत से घर ताश के पतों की तरह एक—दूसरे पर गिरे हुए हैं।" क्रूरता ऐसी है कि शरणार्थियों के जबालया शरणार्थी शिविर पर बमबारी की गई जिसमें 45 लोग मारे गए। उतरी गाजा तो मटियामेट हो ही चुका है अब दक्षिण गाजा जहां शरणार्थी रह रहे हैं, पर भी बमबारी हो रही है। जिस इलाके की यह पत्रकार बात कर रहा है वहां कोई

पच्चीस लाख लोग रहते थे जिन्हें बमबारी के कारण घरबार छोड़ कर भागना पड़ा था। अनुमान है कि गाजा की 80 प्रतिशत जनसंख्या बेघर हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या के लिए बसने की कोई जगह नहीं है और न ही वह वापिस ही आ सके क्योंकि वापिस आने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इजराइल हमास से बदला लेना चाहता है पर बदला बेकध्सूर फिलस्तीनियों से लिया जा रहा है। पिछले 75 वर्षों में इजराइल ने अपने सैनिक बल और पश्चिम के देशों, विशेष तौर पर अमेरिका, के समर्थन से फिलिस्तीन को दुनिया के सबसे बड़े ओपन-एयर जेल में परिवर्तित कर दिया था जहां बाहर से राहत सामग्री भी इजरायल की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती थी। 25 लाख लोग घनी आबादी वाली तंग बस्तियों में रहते हैं जहां इजराइल की खुद्दिया एजेंसियां उन के दैनिक जीवन पर सख्त नजर रखती हैं। जहां पहले रोजाना राहत सामग्री से भरे 500 ट्रक प्रवेश करते थे वहां अब एक दर्जन को मुश्किल से अन्दर आने की इजाजत है। कई लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि इजराइल गाजा के लोगों को भूखा मारना चाहता है, जिसका प्रतिवाद इजराइल कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वह तब तक लड़ते जाएंगे जब तक हमास तबाह नहीं हो जाता। पर अगर वह हमास को तबाह नहीं कर सके तो क्या इसी तरह बेकध्सूर फिलस्तीनियों पर बम और मिसाइल बरसाते रहेंगे? यहूदियों ने अपने इतिहास में यूरोप में बहुत अत्याचार सहा है। हैरानी है कि वैसा ही अत्याचार वह फिलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं।

शिकार अब अत्यंत क्रूर शिकारी बन गया है। इस प्रकार की सरकारी हिंसा तो किसी नस्ली सफाई से कम नहीं। यूनिसेफ ने गाजा की स्थिति को 'मानवीय त्रासदी' कहा है और यह भी कहा है कि गाजा के बच्चों के पास पीने के लिए मुश्किल से पानी की एक बूंद है। वहां अस्पताल काम नहीं कर रहे। अधिकतर तो वैसे ही बमबारी से ध्वस्त हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया है कि वहां भुखमरी की हालत है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई जिस कारण डाक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि जितने बच्चे बमबारी से मारे गए उससे कहीं अधिक बीमारी से मर सकते हैं। इस अंधी क्रूरता पर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जो अब तक इजराइल का समर्थन करते रहे हैं ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के प्रस्ताव को समर्थन दिया है। अमेरिका ने प्रस्ताव को बीटो किया है जबकि भारत समेत 153 देशों ने इसे समर्थन दिया है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वह चाहता है कि वह हमास पर युद्ध की रफतार कम करें पर जब इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो बाइडेन ने पहली बार इजराइल की सख्त आलोचना करते हुए कहा कि वह देश 'अंधाधुंध बमबारी' के कारण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोने की स्थिति में है। पर इसके बावजूद बाइडेन लगातार इजराइल को बम और मिसाइल सप्लाई करते जा रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार युद्ध विराम के पक्ष में वोट डाला है। भारत अभी तक इस मुद्दे पर वोट करने से बचता रहा है। हम 'मानवीय सहायता' या 'युद्ध की तीव्रता कम करने' की वकालत करते रहे हैं।

गाजा क्रिस्तान बनता जा रहा है

संसद को सुरक्षा में संधमारों के चुनावों प्रभाव से बचा नहीं जा सकता



कल्याण शक्ति
2023 का भागीर्थी

2023 का भारताय संसद भवन का सुरक्षा का उल्लंघन पूर्व में 2001 के आतंकवादी हमले के बाद शुरू किये गये पहले से ही कठोर सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगंतुकों की गहन जांच के लिए यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। संसद सदस्यों को पास की अनुशंसा करते समय सतर्क रहना चाहिए और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। घुसपैठियों को भाजपा के मैसूरु संसद की सिफारिश पर पास मिले थे। सरकार ने गहन जांच के आदेश देकर त्वरित प्रतिक्रिया

व्यक्तिया का पकड़ लिया गया है और उन पर कड़े कानूनों के तहत आरोप लगाये गये हैं संसद में हालिया सुरक्षा उल्लंघन के गंभीर राजनीतिक, चुनावी, विधायी और सुरक्षा निहितार्थ हैं। 146 संसदों के अभूतपूर्व निलंबन ने अब विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है। लोकसभा में दो घुसपैठियों को आगंतुक गैलरी से कूदते और लोकसभा के अंदर धुएं के डिब्बे खोलते हुए देखा गया। यह एक रहस्य है कि संसद की सुरक्षा करने वाली पांच स्तरीय सुरक्षा के बावजूद वे सदन में कैसे घुस गये। दुर्भाग्य से, अतीत में विभिन्न देशों

संसद पर हमल हुए ह। इनमें 2018 का स्पेनिश तख्तापलट का आपास, 2017 का यूके संसद पर अतंकवादी हमला, 1987 का श्रीलंकाई संसद ग्रेनेड हमला, 2021 का यूएस पिटोल हमला और अक्टूबर 2023 का तुर्की सरकार भवन पर हमला आमिल है। प्रत्येक मामले में, तुरंत चित्त सुधारात्मक उपाय किये गये। अरतीय संसद पर हुए इस हमले के मामले में, घटना के तुरंत बाद, सुरक्षा गर एक कड़ी कर दी गयी और संसद भवन की किलेबंदी कर दी गयी। हाँ तक कि उल्लंघन की अच्छ-स्तरीय जांच के आदेश भी दिये गये। उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट दिये जाने के बाद और भी कदम ताधये जाने की उम्मीद है। 2023 का भारतीय संसद भवन की सुरक्षा उल्लंघन पूर्व में 2001 के अतंकवादी हमल के बाद शुरू किये गये पहले से ही कठोर सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगंतुकों की हन जांच के लिए यह ध्यान में बना महत्वपूर्ण है। संसद सदस्यों को पास की अनुशंसा करते समय तत्कर रहना चाहिए और उन्हें अपने

उदाहरण
राज्यसभा के
के अधिकार
संसद का

देश
रुना
को
पर
याए
के
हाह
नसे
गा।
दादा
गर
ता।
आ

सभापति की नकल करने और सभापति की अवज्ञा करने के आरोप में कुल 146 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार को अस्वीकार्य बताते हुए यह निर्णय लिया। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी पक्ष का ध्यान सदन चलाने पर नहीं है। अगले महीने होने वाले बजट सत्र में भी टकराव हो सकता है, लेकिन फिर भी लेखा बजट पर मतदान समिति विलापन करना।

के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, पहले कदम के रूप में, विपक्ष ने विपक्षी वोटों को विभाजित होने से बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है।

जहां तक कानून का सवाल है, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये, जबकि निलंबित सदस्यों ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अतीत में भी, कई कानून मिनिटों में पारित कर दिये गये हैं। यहीं दर्जे के एक सम्पूर्ण

पारत किया जाना चाहए। चौंकाने वाले संसद उल्लंघन का चुनावी असर होगा क्योंकि विपक्षी दल मोदी सरकार के कथित अद्वायकवाद के विरोध में एक साथ आये हैं। वे इस मुद्दे को सड़कों पर ले गये हैं और इसे एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बना दिया है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि जब वह संसद जैसी हाई-प्रोफाइल संपत्ति की रक्षा करने में विफल रही तो वह गय था। सुप्राम काट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने एक बार इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि संसद सदस्यों ने पारित किये गये विधों पर पूरी तरह से बहस और चर्चा नहीं की। संसद सदस्यों के पाँच प्राथमिक कार्य हैं—कानून बनाना, बजट की समीक्षा करना, सरकारी गतिविधियों की देखरेख करना, लोगों का प्रतिनिधित्व करना और सरकार को जवाबदेह बनाना।

असरकारी होंगी न्याय यात्रा और नागपुर रेली



करें नागपुर की रैली की। इसी शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है जिसकी विचारधारा का विरोध कांग्रेस प्रारम्भ से ही करती आई है। यहां रैली का आयोजन करना एक तरह से संघ को चुनौती देना तो है ही, यहीं दीक्षाभूमि भी है जहां 14

ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था। अबेंडकर संविदान के निर्माता भी हैं। कांग्रेस की इस दौर की सबसे बड़ी लडाई संविधान को भाजपा द्वारा क्षत-विक्षत होने से बचाने की भी है। इस तरह से देखें तो नागपुर में रैली करने का प्रतीकात्मक

मकस
मोहब्ब
प्रस्तारा
वावर द
जयराम
कि इ
दिया
लोगों
राजनै
जाएगे
हुए ३
किया
लगभग
यात्रा
से हो
से सं
लोगों
विश्वा
सकत
दौरान
प्रतिस

भरोसा है कि इस बार भी पहले जैसा मंजर देखने को मिल सकता है। भाजपा की रीति—नीति के कारण जिस प्रकार से आमजनों के साथ यह सरकार अर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्तरों पर अन्याय कर रही है, उसके चलते कांग्रेस द्वारा इसे न्याय यात्रा का नाम देना उपयुक्त ही प्रतीत होता है। देश में बढ़ती अर्थिक विषमता, महंगाई, बेरोजगारी, जनकल्याण पर घटता खर्च लोगों के साथ हो रहे अन्याय को इंगित करता है। आज अपीरों व सरकार समर्थकों के लिये अलग व्यवस्था है तो समाज में फैलती गैर बराबरी के चलते कमजोर, वचित, शोषित, अल्पसंख्यकों आदि तबकों को न्याय से दूर कर दिया गया है। ऐसे ही, पिछले दिनों संसद में जो कुछ घटा है, वह बतलाता है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को यह सरकार कर्तई बर्दाश्ट

पंचायत है, उसने थोक के भाव में सांसदों को निलम्बित होते देखा है, जो देश के संसदीय इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। सच तो यह है कि देश में दो समाज बना दिये गये हैं—एक कानून को अपनी जूती की नोक के नीचे रखता है, तो दूसरा वह वर्ग है जिसे न्याय की पहुंच से दूर कर दिया गया है। यह यात्रा एक नागरिक के तौर पर भारतीयों को न्याय हासिल कराने का अभियान कही जा सकती है। पहली यात्रा को गैर राजनैतिक कहा गया था, परन्तु यह दूसरी यात्रा अपने सियासी उद्देश्यों को दरकिनार करती हुई आगे नहीं बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव—2024 उसकी आंखों के सामने है और पहली यात्रा में प्राप्त हुई अनेक उपलब्धियों को बरकरार रखने के लिये उसे दूसरी यात्रा को भी सफल बनाना होगा। दोनों यात्राओं के बीच चाहे साल भर का अंतराल आ

'किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू (भारत) के पदाधिकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन'



'ब्यूरो रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव' यूनियन(भारत) के बैनर तले पदाधिकारियों व किसानों ने जय जवान

जय किसान का नारा लगाते हुए विभिन्न समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी स्थानी शुक्रन का ज्ञापन सौंपा है। किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर आदोलन की चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन(भारत) के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आवारा पशुओं को गोशालाओं में संरक्षित किसानों को भी जान गवानी पड़ रही है। गोशालाओं में संरक्षित पशुओं को मानक के मुताबिक चारा

हाड़ कपाऊ ठंड व कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित तीस दिसंबर को इंटर तक रक्खल कालेज बंद रखने के डीएम ने दिये निर्देश



अयोध्या। गुरुवार से कोहरा व हाड़ कंपाने वाली ठंड हवाओं के चलते आम लोगों का जीवन अस्तव्यस्त दिखाई दिया। वही जो लोग

बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे तो वे नौकरी पावा वाले या फिर मजबूरी में किसी काम के चलते अपने घरों से निकले हुए दिखाई रहे थे गुरुवार को कोहरे का असर इतना अधिक दिखाई दे रहा था कि उस दिन मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर नहीं उत्तरने के चलते उनका कार्यक्रम उस दिन निरस्त करना पड़ा था। गुरुवार से अधिकतर स्कूलों के बच्चे इस ठंड में सुबह कापते हुए स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वही नगर निगम कार्मियों की माने तो शिश्रृंखला ही शहर में चिन्हित जगहों पर अलावा की व्यवस्था की जायेगी।

हर विद्यानसमा से 25 से 30 हजार लोगों को दिया जा रहा है पीएम की रैली के लिए आमंत्रण

डिप्टी सीएम और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में की समीक्षा बैठक

अयोध्या। (डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित महरेली की तैयारियों की समीक्षा उपर्युक्तमंत्री केशव प्रसाद मोर्याव व क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने सर्किट हाउस में किया। समीक्षा के दौरान सांसद ललूर सिंह व महापौर परिषेष पाति त्रिपाठी, विद्यायक वेद प्रकाश गुटा, रामचन्द्र यादव, अमित सिंह

चौहान, प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष संस्कृत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, अपेक्षक मिश्रा, अवधेश पाण्डेय बादल आदि की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन से हर विद्यानसमा में दो पदाधिकारियों की भी जानसम्पर्क अभियान में लगाया गया है। इसके साथ में चार पहिया बाहन, मोटरसाईकिल से भी लोग आएंगे।

खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है : मनीष सिंह



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। एसकेडी अकादमी

की गोमती नगर और राजाजीपुरम स्थित सभी शाखाओं में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को समूह के निदेशक मनीष सिंह के द्वारा प्रथम पुरस्कार एवं संगठन के अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुआ। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर प्रतिमाओं की खोज एवं उनका संवर्धन करना है। इस अवसर पर समूह की उपस्थिति रही। जिलाध्यक्ष संनीव सिंह ने बताया कि विद्यानसमा 25 से 30 हजार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को खेलकूद से निवेशक करते हुए समूह के संवेदित निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि खेलकूद से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास और टीम भाजपा की जागृत होती है। उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य किताबी शिक्षा से ऊपर